



# निपाह वायरस को लेकर झारखंड सरकार अलर्ट, सिविल सर्जनों को सतर्क रहने के निर्देश



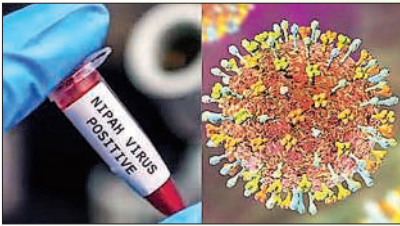
प्रत्युष नवबिहार संवाददाता

**रांची :** पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के दो संदिग्ध मामलों के सामने आने के बाद झारखंड सरकार पूरी तरह सतर्क हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने मंगलवार को प्रदेश के सभी जिलों के सिविल सर्जनों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह को भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि निपाह वायरस एक अत्यंत खतरनाक जूनोटिक बीमारी है, जो जानवरों से मनुष्यों में फैलती है। यह वायरस

मुख्य रूप से फल खाने वाले चमगादड़ों (फ्रूट बैट) से फैलता है। इसके अलावा संक्रमित जानवरों, विशेषकर सूअरों के सीधे संपर्क, उनके संक्रमित मांस के सेवन अथवा संक्रमित व्यक्ति के शरीर से निकलने वाले लार, रक्त और अन्य द्रवों के संपर्क में आने से भी संक्रमण फैल सकता है। डॉ. इरफान अंसारी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि राज्य के सभी जिलों में सख्त निगरानी, त्वरित रिपोर्टिंग प्रणाली और जन-जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं, ताकि लोगों को निपाह वायरस के लक्षण, बचाव और आवश्यक सावधानियों की पूरी जानकारी मिल सके और राज्य में इसके

## 24 घंटे निगरानी में निपाह संक्रमित पश्चिम बंगाल की दो नर्सों, हालत गंभीर

**कोलकाता :** निपाह वायरस से संक्रमित पश्चिम बंगाल की दो नर्सों की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। दोनों बारासात इलाके के एक अस्पताल में कार्यरत हैं और वहीं के आईसीयू आइसोलेशन वार्ड में उनका इलाज चल रहा है। अस्पताल में कोविड काल के दौरान लागू की गई सभी गाइडलाइनों को फिरे से सख्ती से लागू किया गया है। संक्रमित नर्सों में से एक पूर्व बर्धमान जिले की निवासी हैं, जबकि दूसरी नंदिया जिले से हैं। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक, दोनों 5 जनवरी से शारीरिक रूप से अस्वस्थ थीं। उनकी स्थिति पर 24 घंटे कड़ी नजर रखी जा रही है। फिलहाल, स्थिति में न तो कोई गिरावट आई है और न ही अब तक कोई सुधार देखा गया है। संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए अस्पताल प्रशासन ने सख्त एहतियाती कदम उठाए हैं। निर्देश के तहत अस्पताल के सभी कर्मचारी और चिकित्सकों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। सुरक्षा कर्मियों और मरीजों के परिजनों पर भी यही नियम लागू किया गया है। निपाह संक्रमित स्वास्थ्यकर्मियों के इलाज में लगे डॉक्टरों और स्टाफ को पीपीई किट पहनकर ड्यूटी करनी पड़ रही है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को सहयोग देने के लिए एक राष्ट्रीय संयुक्त आउटब्रेक प्रतिक्रिया टीम तैनात की है। इस टीम में कोलकाता स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड पब्लिक हाइजीन, पुणे का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (एनआईवी), चेन्नई का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी (एनआईई), एम्स कल्याणी तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन्यजीव विभाग के विशेषज्ञ शामिल हैं।



किसी भी संभावित प्रकोप को रोकना जा सके। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार इस खतरनाक बीमारी की रोकथाम के लिए पूरी तरह मुस्तैद है और स्वास्थ्य विभाग को हर स्तर पर सतर्क रहने के निर्देश दिए गए

हैं। विज्ञप्ति में बताया गया है कि निपाह वायरस की मृत्यु दर (फैटैलिटी रेट) काफी अधिक होती है, जो प्रकोप की गंभीरता के अनुसार 40 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक हो सकती है। इसी कारण इसे एक अत्यंत गंभीर और घातक रोग

माना जाता है। निपाह वायरस के प्रमुख लक्षणों में तेज बुखार, सिरदर्द, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, गले में खराश, मानसिक भ्रम, मस्तिष्क पर गंभीर प्रभाव (एन्सेफलाइटिस) और कोमा जैसी गंभीर स्थितियां शामिल हैं।

## धरती आबा की बेटियों की आत्मनिर्भरता से परिचित होगी दुनिया : कल्पना सोरेन

प्रत्युष नवबिहार संवाददाता

**रांची :** विश्व आर्थिक सम्मेलन 2026 में पहली बार झारखण्ड की उपस्थिति कई मायनों में अहम है। झारखण्ड औद्योगिक क्षमता और इनफि नाइट ऑपरेटिविटी स्टेट का संदेश तो देगा ही साथ ही, यह भी स्पष्ट करेगा कि जब आधी आबादी नेतृत्व करती हैं, तो अर्थव्यवस्थाएं मजबूत होती हैं, लोग अप्रत्याशित बदलावों का सामना करने वाले बनते हैं और विकास स्थायी होता है। कुछ ऐसा ही संदेश झारखण्ड की बेटी और झारखण्ड विधानसभा के महिला एवं बाल विकास समिति की अध्यक्ष सह विधायक कल्पना सोरेन दावोस में आयोजित होने वाली विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में और यूनाइटेड किंगडम की अपनी यात्रा के दौरान वैश्विक मंच से देंगी। कल्पना सोरेन महिला नेतृत्व, लैंगिक समानता और समावेशी विकास से संबंधित कई उच्च स्तरीय मंचों पर राज्य का प्रतिनिधित्व कर झारखण्ड की आधी आबादी के आत्मविश्वास, उद्यमशीलता और नेतृत्व कौशल का प्रमाण प्रस्तुत करेंगी। वे आदिवासी, ग्रामीण और आर्थिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों की महिलाओं की



वास्तविकताओं और आकांक्षाओं को वैश्विक मंच पर साझा कर बतायेंगी कि ये वे समूह हैं जो अब झारखण्ड के आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की वाहक बन रहीं हैं।

### महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में झारखण्ड सरकार राज्य की महिलाओं के उत्थान के लिए कई कार्य कर रही है। उसी कड़ी में दावोस में कल्पना सोरेन महिलाओं के राजनीतिक नेतृत्व, आर्थिक भागीदारी और सभी को समान अवसर देने पर केंद्रित नीतिगत संवादों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों से संबोधित करेंगी। इनमें महिला सशक्तिकरण पर ब्रिक्स

पैनल, ईटी महिला सशक्तिकरण संवाद और एलार्स फॉर ग्लोबल गुड का 'वी लीड' मंच और भारत पवेलियन में आधिकारिक कार्यक्रम आदि शामिल हैं। राज्य सरकार का महिला विकास के प्रति दृष्टिकोण कल्पना सोरेन इन वैश्विक मंचों पर प्रस्तुत करेंगी। वे बतायेंगी कि महिला विकास प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व पर आधारित नहीं है, बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण और संस्थागत शक्ति पर आधारित है।

### ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहीं महिलाएं

दावोस में दुनिया को बताया जाएगा कि झारखण्ड राज्य आजीविका संवर्धन समिति के माध्यम से राज्य में 35 लाख से अधिक महिलाएं दो लाख 80 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। हाल के वर्षों में इन महिलाओं के सशक्तिकरण एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से ₹5000 करोड़ से अधिक का ऋण स्वीकृत किया गया है। ये महिलाएं अब किसान, उद्यमी, बैंकर, कारीगर और विभिन्न आजीविका की सृजनकर्ता के साथ सम्मानजनक जीवन यापन करने वाली हैं।

### एक नजर

**रामेश्वरम के 10 मछुआरों को श्रीलंका की नौसेना ने हिरासत में लिया**

चेन्नई : श्रीलंका की नौसेना ने रामेश्वरम के 10 मछुआरों को हिरासत में लिया है। इस दौरान एक मछली पकड़ने वाली नाव को पकड़ा है। तमिलनाडु और पुदुचेरी के मछुआरों को सीमा पर मछली पकड़ने के आरोप में श्रीलंकाई नौसेना द्वारा गिरफ्तार किया जाना और उनकी नौकाओं को जप्त कर सरकारी संपत्ति घोषित किए जाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इससे मछुआरों की आजीविका गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। इसी क्रम में, नेदुनथीवु (क्षेत्र में सीमा पर मछली पकड़ने के आरोप में रामेश्वरम के 10 मछुआरों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि मछुआरों को जाफना मत्स्य विभाग के अधिकारियों के समक्ष पेश किया जाएगा। मछुआरों की गिरफ्तारी से उनके परिवारों और मछुआरा समुदाय में आक्रोश फैल गया है। आरोप लगाया गया है कि श्रीलंकाई नौसेना ने अतिक्रमण करते हुए कार्रवाई की है, मछुआरों की तत्काल रिहाई की मांग की जा रही है।

## चीन-पाकिस्तान को आर्मी चीफ की दो टूक, 1963 का समझौता अवैध, शक्सगाम घाटी में दखल बर्दाश्त नहीं



एजेंसी

**नयी दिल्ली :** भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, पाकिस्तान और चीन के बीच 1963 के समझौते को भारत गैर-कानूनी मानता है। इसलिए, शक्सगाम घाटी में किसी भी गतिविधि को हम मंजूरी नहीं देते हैं। इस संबंध में विदेश मंत्रालय पहले ही बयान जारी कर चुका है। इसलिए, चीन में जो संयुक्त बयान जारी किया गया है, CPEC 2.0 के बारे में मैं जो समझता हूँ, हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं, और हम इसे दोनों देशों (चीन-पाकिस्तान) द्वारा की जा रही एक गैर-कानूनी कार्रवाई मानते हैं। चीन ने भारत की आपत्तियों के बीच सोमवार को

शक्सगाम घाटी पर अपने क्षेत्रीय दावों को दोहराया। और कहा कि इस इलाके में उसकी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं बिल्कुल उचित हैं। चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) को लेकर भारत द्वारा आलोचना किए जाने पर चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने बीजिंग के पुराने रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि यह एक आर्थिक पहल है, जिसका उद्देश्य स्थानीय आर्थिक व सामाजिक विकास करना और लोगों की जीवन में सुधार लाना है।

### शक्सगाम घाटी को भारत ने बताया अपना क्षेत्र

भारत ने पिछले शुक्रवार को

शक्सगाम घाटी में चीन की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आलोचना करते हुए कहा था कि यह भारतीय क्षेत्र है। डूंगन और पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा, उसके पास अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, शक्सगाम घाटी भारतीय क्षेत्र है। हमने 1963 में किए गए तथाकथित चीन-पाकिस्तान 'सीमा समझौते' को कभी मान्यता नहीं दी है। हम लगातार कहते आए हैं कि यह समझौता अवैध और अमान्य है। उन्होंने कहा, हम तथाकथित चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) को भी मान्यता नहीं देते, क्योंकि यह भारतीय क्षेत्र से होकर गुजरता है, जिसपर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। पाकिस्तान ने 1963 में अवैध रूप से कब्जाए गए भारतीय क्षेत्र में से शक्सगाम घाटी के 5180 वर्ग किलोमीटर हिस्से को चीन को सौंप दिया था।

एजेंसी

**नयी दिल्ली :** केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया की सख्त पहल के बाद क्विक कॉमर्स कंपनी ब्रिंकिट ने अपने सभी ब्रांड प्लेटफॉर्मों से '10 मिनट में डिलीवरी' का दावा पूरी तरह हटा दिया है। यह फैसला डिलीवरी वर्कर्स की सुरक्षा और बेहतर कामकाजी हालात को ध्यान में रखकर लिया गया है।

### केंद्र सरकार की सख्त सलाह के बाद दावा हटाया

केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने ब्रिंकिट, जेटो, स्विगी और जोमैटो के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने इन कंपनियों को सलाह दी कि सख्त डिलीवरी टाइम लिमिट को हटाया जाए, ताकि डिलीवरी पार्टनर्स की जान को खतरा न हो और वे सुरक्षित तरीके से काम कर सकें। बैठक में सभी कंपनियों ने सरकार को भरोसा दिया कि वे अपने ब्रांड विज्ञापनों, सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्मों से डिलीवरी टाइम



की सख्त कमिटमेंट हटा देंगे। ब्रिंकिट ने तुरंत यह बदलाव लागू कर दिया है, जबकि बाकी कंपनियां भी जल्द ही ऐसा करने वाली हैं।

### क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्मों ने क्यों लिया फैसला ?

पिछले कुछ हफ्तों में गिग वर्कर्स यूनियनों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और स्ट्राइक की थीं। उन्होंने 10-20 मिनट की अल्ट्रा-फास्ट डिलीवरी मॉडल को असुरक्षित बताया था, क्योंकि इससे डिलीवरी पार्टनर्स को तेज रफ्तार से गाड़ी चलानी पड़ती है,

जिससे एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। यूनियनों ने न्यू इयर ईव (31 दिसंबर 2025) पर भी स्ट्राइक की थी और श्रम मंत्री को जापन सौंप था।

सरकार ने इन चिंताओं को गंभीरता से लिया और कंपनियों से बातचीत की। यह कदम डिलीवरी वर्कर्स के लिए एक बड़ी राहत है, जो रोजाना सड़कों पर जान जोखिम में डालकर काम करते हैं। यह बदलाव क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री में एक अहम मोड़ है, जहां पहले स्पीड को सबसे बड़ा आकर्षण बनाया जाता था, लेकिन अब वर्कर्स की सुरक्षा को

## 'सनातन धर्म को मिटाना आसान नहीं, ये सूरज और चांद की तरह अमर', सोमनाथ मंदिर को लेकर बोले शाह

एजेंसी

**गांधीनगर :** केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि भारत के सनातन धर्म, संस्कृति, लोगों की आस्था को खत्म करना आसान नहीं है। अमित शाह ने सोमनाथ मंदिर के बीती सदियों में बार-बार तोड़े जाने और 16 बार पुनर्निर्माण का हवाला दिया। शाह ने कहा कि जिन लोगों ने सोमनाथ मंदिर पर हमले किए, वो मिट गए, लेकिन मंदिर आज भी उसी जगह पर पूरे गर्व के साथ खड़ा है।

### 'सनातन धर्म, सूरज और चांद की तरह शाश्वत और अमर'

अमित शाह गुजरात दौरे पर हैं। मंगलवार को अमित शाह ने गांधीनगर में 267 करोड़ रुपये की



विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। शाह ने कहा, '16 बार तबाह किए जाने के बावजूद सोमनाथ मंदिर 1000 साल बाद भी पूरे गर्व और सम्मान के साथ खड़ा है और इसके शीर्ष पर धर्मध्वजा लहरा रही है।' गृह मंत्री ने कहा, 'ये पूरी दुनिया के लिए संदेश है कि भारत के सनातन धर्म, संस्कृति और लोगों की आस्था को

मिटाना आसान नहीं है। यह चांद और सूरज की तरह शाश्वत और अमर है। सोमनाथ मंदिर भारत की आस्था, विश्वास और गर्व का प्रतीक है।'

### पीएम मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का शुभारंभ किया

बीती 11 जनवरी को पीएम मोदी

ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का शुभारंभ किया था। यह पर्व सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी के हमले और मंदिर के पुनर्निर्माण के 1000 हजार साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। महमूद गजनी ने साल 1026 में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर के भव्य कॉरिडोर निर्माण किया जाएगा। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पूरे सालभर देश में मनाया जाएगा। इस दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और लोगों को जागरूक किया जाएगा।

### 'मंदिर पर हमला हमारी आस्था पर हमला था'

शाह ने कहा, 'एक हजार साल

पहले महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और इसे तोड़ा। उसके बाद अन्य हमलावरों जैसे अलाउद्दीन खिलजी, अहमद शाह, महमूद बेगड़ा और औरंगजेब ने भी हमले किए, लेकिन हर हमले के बाद मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। हमलावर तबाही में विश्वास रखते थे और मंदिर बनाने वालों का विश्वास रचना में। आज 1000 साल बाद हमलावर मिट गए हैं, लेकिन सोमनाथ मंदिर अभी भी पूरे गर्व के साथ खड़ा है।' गृह मंत्री ने कहा, 'सोमनाथ मंदिर पर हमला सिर्फ एक मंदिर पर हमला नहीं था बल्कि ये हमारी आस्था, विश्वास और आत्म सम्मान पर हमला था। हमले का जवाब दूसरा हमला नहीं हो सकता। इसका उत्तर आत्म-सम्मान में छिपा है।'

## ‘सफेदपोश’ आतंकी मॉड्यूल के खुलासे के बाद कश्मीर में मस्जिदों और मदरसों की प्रोफाइलिंग शुरू

एजेंसी

**श्रीनगर :** पिछले वर्ष ‘सफेदपोश’ आतंकी मॉड्यूल के भंडाफोड़ के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने कश्मीर घाटी में मस्जिदों, मदरसों तथा इन धार्मिक संस्थानों से जुड़े प्रबंधनकर्ताओं, इमामों और शिक्षकों की प्रोफाइलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि मस्जिदों, मदरसों, इमामों (नमाज के अनुआ), शिक्षकों और इन संस्थानों की प्रबंधन समितियों से जुड़े व्यक्तियों का विवरण एकत्र करके विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें निर्माण कार्यों के लिए प्रयुक्त धन के स्रोतों और दैनिक खर्चों से



जुड़ी जानकारी शामिल है। अधिकारियों के अनुसार, सामान्य विवरण के अलावा मदरसों के शिक्षकों और इमामों से आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, संपत्ति स्वामित्व, सोशल मीडिया हैंडल, पासपोर्ट, एटीएम कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सिम कार्ड, मोबाइल फोन नंबर और आईएमईआई नंबर जैसी विस्तृत जानकारी भी मांगी गई है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस अभियान का उद्देश्य मस्जिदों,

मदरसों और उनसे जुड़े व्यक्तियों का एक समग्र और अद्यतन डेटाबेस तैयार करना है। उल्लेखनीय है कि नवंबर 2025 में ‘सफेदपोश’ आतंकी मॉड्यूल के भंडाफोड़ के दौरान जांच में यह सामने आया था कि कुछ संदिग्धों को मदरसों या सोशल मीडिया के माध्यम से कट्टरपंथी बनाया गया था। अधिकारियों के अनुसार, मौलवी इरफान सहित कुछ इमामों की संदिग्ध भूमिका के चलते वे जांच के दायरे में आए थे।















### रुपया गिरावट पर बंद

मुंबई ।

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मंगलवार को भारतीय रुपया 7 पैसे की गिरावट के साथ ही 98.24 पर बंद हुआ। आज सुबह शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया पांच पैसे कमजोर होकर 90.22 पर पहुंच गया। आज अमेरिकी डॉलर की मजबूती, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और विदेशी निवेशकों की लगातार पूंजी निकासी के कारण भी रुपया नीचे आया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 90.24 प्रति डॉलर पर खुला। शुरुआती सत्र में इसमें हल्की मजबूती जरूर देखने को मिली, लेकिन यह 90.22 के स्तर तक ही सीमित रही, जो पिछले बंद भाव की तुलना में पांच पैसे की गिरावट को दिखाता है। इससे पहले सोमवार को रुपया 90.17 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इस बीच छह प्रमुख वैश्विक मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.11 फीसदी की बढ़त के साथ 98.73 पर बना रहा। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक संकेतों के चलते निकट भविष्य में रुपये में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है।

### इंडिगो की न्यू ईयर सेल, घरेलू फ्लाइट 1,499 से शुरू



नई दिल्ली ।

इंडिगो ने मंगलवार को अपनी न्यू ईयर सेल की घोषणा की है। यह सेल 13 जनवरी से 16 जनवरी तक चलेगी। सेल के तहत घरेलू मार्गों पर सभी कर और शुल्क शामिल 1,499 रुपए से टिकट उपलब्ध होंगे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर किराया 4,499 रुपए से शुरू होगा, जिससे यात्रियों को सस्ती फ्लाइट का लाभ मिलेगा। इंडिगो ने यह भी बताया कि चुनिंदा 6ई एंजऑन पर 70 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। इसमें अतिरिक्त सेवाएं जैसे सीट चयन और अतिरिक्त बैगेज शामिल हो सकते हैं। यात्री इस सीमित अवधि में बुकिंग कर अपनी यात्रा को फायती बना सकते हैं।

### एचसीएल टेक्नॉलजीज का मुनाफा घटा, राजस्व में बढ़त जारी

नई दिल्ली ।

भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी एचसीएल टेक्नॉलजीज का तीसरी तिमाही का मुनाफा 4,076 करोड़ रुपए रहा, जो सालाना आधार पर 11.1 फीसदी कम है। कंपनी ने बताया कि नवंबर में लागू नई श्रम संहिता के तहत कर्मचारी लाभों के लिए 956 करोड़ रुपए अलग रखना पड़ा, जिससे मुनाफा प्रभावित हुआ। कंपनी का राजस्व सालाना आधार पर 13.3 फीसदी बढ़कर 33,872 करोड़ रुपए हुआ। वित्तीय सेवाओं और विनिर्माण क्षेत्रों से मदद मिली। स्थिर मुद्रा आधार पर राजस्व में 8.1 फीसदी की वृद्धि रही और तिमाही आधार पर 6 फीसदी का सुधार हुआ। राजस्व बाजार अनुमान से बेहतर रहा, जबकि मुनाफा उम्मीद से कम रहा। एचसीएल अब स्थिर मुद्रा में 4-4.5 फीसदी वृद्धि की उम्मीद कर रही है। सेवाओं से राजस्व में 4.75-5.25 फीसदी की बढ़त अनुमानित है।

## अश्विनी वैष्णव ने अमेरिका में खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं और एआई सहयोग पर जोर दिया

वैष्णव ने वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट द्वारा आयोजित खनिज आपूर्ति श्रृंखला मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया

नई दिल्ली ।

रेल, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अमेरिका में वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया। उन्होंने भारत की विनिर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षमता को मजबूत करने के लिए खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुस्था को आवश्यक बताया। वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा कि विकसित भारत के

लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण है। बैठक में अमेरिका सहित ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, फ्रांस और जर्मनी के वित्त मंत्री और उच्च अधिकारी मौजूद थे। अमेरिकी वित्त मंत्री बेसेंट ने कहा कि राष्ट्रों को निवेशपूर्ण जोखिम-निवारण उपाय अपनाकर आपूर्ति श्रृंखलाओं की कमजोरियों को दूर करना चाहिए। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने भी यह स्पष्ट किया कि उन्होंने पहले से किए गए निवेशों और योजनाओं के माध्यम से मजबूत, सुरक्षित और विविध



आपूर्ति श्रृंखला बनाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इस दौरान वैष्णव ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति कार्यालय के निदेशक माइकल कैंट्रियसोस और

भारतीय राजदूत विनय क्रात्रा से मुलाकात की। बैठक में भारत में फरवरी 2026 में आयोजित होने वाले ई डिया एआई इम्पेक्ट से मिट पर चर्चा हुई।

## देश की खुदरा महंगाई दिसंबर में बढ़ी, फिर भी आरबीआई की सीमा के नीचे

कम महंगाई का मुख्य कारण खाद्य वस्तुओं की कीमतों में गिरावट रही

नई दिल्ली ।

दिसंबर में देश की खुदरा महंगाई दर (सीपीआई) 1.33 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो नवंबर में 0.7 प्रतिशत थी। यह बीते तीन महीनों का उच्चतम स्तर माना जा रहा है। हालांकि, यह अभी भी भारतीय रिजर्व बैंक की निचली सहनशील सीमा 2 प्रतिशत से नीचे है। साल 2025 में औसतन महंगाई दर लगभग 2.2 प्रतिशत रही, जो पिछले एक दशक में सबसे कम

स्तरों में से एक है। इस कम महंगाई का मुख्य कारण खाद्य वस्तुओं की कीमतों में गिरावट रही। दिसंबर में खाद्य महंगाई लगातार सातवें महीने नकारात्मक रही, लेकिन -3.9 प्रतिशत से -2.71 प्रतिशत पर सुधरी। अनाज में 51 महीनों के बाद पहली बार गिरावट दर्ज की गई। सब्जियां और दालें लगातार 11वें महीने सस्ती रही, जबकि तेल और फलों की कीमतें भी कई महीनों के निचले स्तर पर रही। खाद्य और ईंधन को

छोड़कर कोर महंगाई दिसंबर में 4.8 प्रतिशत तक बढ़ गई, जो 28 महीनों का उच्चतम स्तर है। यदि सोना-चांदी को हटाया जाए, तो कोर महंगाई 2.4 प्रतिशत पर स्थिर है। पर्सनल के यर महंगाई 2.8 प्रतिशत तक पहुंच गई, जबकि घरेलू सामान, स्वास्थ्य और परिवहन क्षेत्रों में महंगाई कई सालों के निचले स्तर पर है।

जनवरी 2026 से नया 2024 आधार वर्ष लागू होगा, जिसमें गैर-खाद्य वस्तुओं का वजन बढ़ाया

गया है। इससे महंगाई आंकड़ों में बदलाव आने की संभावना है। मौद्रिक नीति पर असर की बात करें तो, महंगाई लक्ष्य से नीचे और कोर दबाव सीमित रहने के कारण आरबीआई की फरवरी बैठक में 25 बेसिस प्वाइंट दर कटौती की संभावना बढ़ गई है।

हालांकि, कुछ विशेषज्ञ नए सीपीआई और जीडीपी डेटा का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले महीनों में महंगाई में हल्की बढ़त देखने को मिल सकती है।

## भारत का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात 2025 में 4 लाख करोड़ के पार-केंद्रीय मंत्री वैष्णव देश का इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन लगभग 11.3 लाख करोड़ और निर्यात 3.3 लाख करोड़ रुपए रहा

नई दिल्ली ।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात 2025 में चार लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2024-25 में देश का इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन लगभग 11.3 लाख करोड़ रुपये और निर्यात करीब 3.3 लाख करोड़ रुपये रहा। मंत्री ने कहा कि चार नए सेमीकंडक्टर संयंत्रों के उत्पादन शुरू होने के बाद 2026 में निर्यात में और वृद्धि होने की उम्मीद है। देश के इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में मोबाइल फोन

का दबदबा है। 2024-25 में मोबाइल फोन का उत्पादन 5.5 लाख करोड़ रुपये और निर्यात लगभग 2 लाख करोड़ रुपये रहा। उद्योग निकाय इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के अनुसार, 2025-26 के अंत तक मोबाइल फोन का उत्पादन 75 अरब अमेरिकी डॉलर (6.76 लाख करोड़ रुपये) तक पहुंचने का अनुमान है, जिसमें 30 अरब अमेरिकी डॉलर (2.7 लाख करोड़ रुपये) का निर्यात शामिल है। मंत्री ने बताया कि भारत से आईफोन का निर्यात 2025 में 2.03 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो

2024 में 1.1 लाख करोड़ रुपये था। काउंटरपॉइंट के एक प्रमुख अेधिकारी के अनुसार एप्पल ने भारत में अपने विनिर्माण का विस्तार कर निर्यात को रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचाया है। भारत में उत्पादित हर चार स्मार्टफोन में से एक का निर्यात किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में लगभग 25 लाख लोग कार्यरत हैं। निर्यात और उत्पादन ने रोजगार सृजन के साथ-साथ विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी मदद की। एप्पल की प्रीमियम और सुपर-प्रीमियम श्रेणियों में अग्रणी स्थिति ने देश के स्मार्टफोन बाजार की वृद्धि को गति



दी है। 2026 में सेमीकंडक्टर संयंत्रों के उत्पादन शुरू होने से निर्यात और उत्पादन में और वृद्धि की उम्मीद है, जिससे भारत की वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल बाजार में स्थिति और मजबूत होगी।

## शेयर बाजार गिरावट पर बंद सेंसेक्स 250 अंक , निफ्टी 57 अंक नीचे आया

मुंबई ।

भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को गिरावट पर बंद हुआ। सप्ताह के दूसरे ही कारोबारी दिन बाजार में ये गिरावट दुनिया भर से मिले कमजोर संकेतों के साथ ही बिकवाली हावी रहने से आई है। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स अंत में 250.48 अंक टूटकर 83,627.69 जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 57.95 अंक फिसलकर 25,732.30 पर बंद हुआ। बाजार को हालांकि पीएसयू बैंकों ने सहारा दिया। निफ्टी पीएसयू बैंक , निफ्टी मीडिया, निफ्टी आईटी, निफ्टी सर्विसेज , निफ्टी मेटल बढ़त के साथ बंद हुआ जबकि निफ्टी इन्फ्रा , निफ्टी इंडिया डिफेंस , निफ्टी कंज्यूम ड्यूरेबल्स, निफ्टी रियल्टी और निफ्टी फार्मा गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं मिडकैप और स्मॉलकैप में मिलाजुला कारोबार

हुआ। सेंसेक्स पैक में टेक महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक , एसबीआई , टीसीएस, बजाज फिनसर्व, इन्फोसिस, एनटीपीसी, एचडीएफसी बैंक और पावर ग्रिड के शेयर लाभ में रहे जबकि ट्रेड, एलएंडटी, इंडिगो, माहूति सुजुकी, आईटीसी, बीईएल, एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल, एचयूएल, एमएंडएम, अल्ट्राटेक सोमेंट, सन फार्मा, एशियन पेंट्स और टाटा स्टील नुकसान में रहे। माना जा रहा है कि ईरान के साथ ट्रेड करने वाले देशों पर संपावित अमेरिकी टैरिफ को लेकर नई चिंताओं के कारण घरेलू बाजार में गिरावट आई। वहीं इससे पहले आज सुबह बाजार मजबूती के साथ खुले। हालांकि, शुरुआती बढ़त ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी। कुछ ही देर में मुनाफाखुली और नकारात्मक वैश्विक संकेतों के चलते यह गिरावट में आ गया। सुबह शुरुआत के बाद सेंसेक्स195.79 अंक की गिरावट

### टीसीएस का मुनाफा घटा, राजस्व अनुमान से बेहतर नई दिल्ली ।

देश की प्रमुख आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने चालू वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में आय के मोर्चे पर विश्लेषकों के अनुमान से बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन मुनाफे में गिरावट दर्ज की गई। कंपनी का शुद्ध मुनाफा साल-दर-साल आधार पर 13.9 फीसदी घटकर 10,657 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 12,380 करोड़ रुपये था। सितंबर तिमाही के मुकाबले मुनाफे में 11.7 फीसदी की कमी आई है। वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में टीसीएस की कुल आय 4.8 फीसदी बढ़कर 67,087 करोड़ रुपये रही। तिमाही-दर-तिमाही आधार पर आय में 2 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। यह आंकड़ा ब्लूमबर्ग के 66,849 करोड़ रुपये के अनुमान से अधिक रहा, हालांकि मुनाफा अनुमानित 13,005 करोड़ रुपये से कम रहा। भौगोलिक स्तर पर उत्तर अमेरिका में आय 0.1 फीसदी और लैटिन अमेरिका में 4.6 फीसदी बढ़ी। यूरोप में 2.1 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि ब्रिटेन में आय 1.9 फीसदी घटी। स्थिर मुद्रा आधार पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कुल वृद्धि महज 0.5 फीसदी रही।

## शेयर बाजार गिरावट पर बंद सेंसेक्स 250 अंक , निफ्टी 57 अंक नीचे आया



के साथ 83,682.38 अंक पर वहीं निफ्टी भी 25,897 के स्तर पर मजबूत शुरुआत करने के बाद फिसल गया। सुबह खुलने के बाद निफ्टी 60.40 अंक टूटकर 25,729.85 पर ट्रेड करता दिखा। वहीं एशियाई शेयर बाजारों में तेजी देखी गई। निवेशकों ने ईरान और वेनेजुएला में भू-राजनीतिक तनावों और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल के खिलाफ आपराधिक जांच को फिलहाल नजरअंदाज किया। चीन का

सीएसआई

300 इंडेक्स 0.54 फीसदी बढ़ा। हागकांग का हैंग सेंग 1.32 फीसदी चढ़ा, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.04 फीसदी ऊपर रहा। जापान का निक्केई 3.22 फीसदी उछल गया। वॉल स्ट्रीट पर भी मजबूती रही। एसएंडपी 500 और डाउ जोस रातों-रात नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए। एसएंडपी 500 में 0.16 फीसदी, डाउ जोस में 0.17 फीसदी और नैस्डैक में 0.26 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई।

### महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के चलते 15 जनवरी को शेयर बाजार बंद रहेंगे

मुंबई ।

महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों के चलते 15 जनवरी को भारतीय शेयर बाजार बंद रहेंगे। इसे दिन बीएसई और एनएसई दोनों एक्सचेंजों पर कोई ट्रेडिंग नहीं होगी। पहले यह दिन



केवल सेटलमेंट हॉलिड था, लेकिन अब नए सर्कुलर के अनुसार पूरे कैपिटल मार्केट सेगमेंट में छुट्टी घोषित की गई है। इस दिन इक्रिटी और इक्रिटी डेरिवेटिव्स, सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोइंग, करेंसी और इंटररेस्ट रेट डेरिवेटिव्स एवं कर्मांडी डेरिवेटिव्स में केवल सुबह का सत्र रह रहेगा। शेयर बाजार 2026 में कई अवसरों पर बंद रहेगा, जिनमें गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), होली (3 मार्च), श्री राम नवमी (26 मार्च), गुड फ्राइड (3 अप्रैल), महाराष्ट्र दिवस (1 मई), गणेश चतुर्थी (14 सितंबर), दशहरा (20 अक्टूबर), दीवाली बलिप्रतिपदा (10 नवंबर) और क्रिसमस (25 दिसंबर) शामिल हैं। इसके अलावा सप्ताहांत यानी शनिवार और रविवार पर भी निर्धारित ट्रेडिंग नहीं होती।

### मुकेश अंबानी ने गुजरात में की रिलायंस के पांच बड़े कमिटमेंट्स की घोषणा

5 साल में 7 लाख करोड़ का निवेश करेगी रिलायंस



मुंबई ।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्ग्रेस में गुजरात के लिए पांच महत्वपूर्ण कमिटमेंट्स की घोषणा की। उन्होंने बताया कि पिछले पांच साल में रिलायंस ने राज्य में 3.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है और अगले पांच साल में इसे 7 लाख करोड़ रुपये तक दोगुना किया जाएगा। इस निवेश का उद्देश्य बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करना और लोगों की आजीविका को मजबूत करना है। मुकेश अंबानी ने बताया कि जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा इंटिग्रेटेड क्लीन एनर्जी इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। इसमें सोलर पावर, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन फर्टिलाइजर, सस्टेनेबल एंक्विशन और एडवांस्ड मटीरियल्स शामिल होंगे। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य जामनगर को भारत का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी और ग्रीन मटीरियल्स

एक्सपोर्ट हब बनाना है। रिलायंस कच्छ में मल्टी-गोवावर्ट , यूटिलिटी-स्कैले सोलर प्रोजेक्ट विकसित करेगा। यह प्रोजेक्ट चौबीसों घंटे क्लीन पावर सप्लाई के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी क्लीन एनर्जी परियोजनाओं में से एक बताया गया है। जामनगर में भारत का सबसे बड़ा एआई-रेडी डेटा सेंटर बनाया जाएगा। जियो क्राइड रुपये तक दोगुना किया जाएगा। इस निवेश का उद्देश्य बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करना और लोगों की आजीविका को मजबूत करना है। मुकेश अंबानी ने बताया कि जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा इंटिग्रेटेड क्लीन एनर्जी इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। इसमें सोलर पावर, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन फर्टिलाइजर, सस्टेनेबल एंक्विशन और एडवांस्ड मटीरियल्स शामिल होंगे। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य जामनगर को भारत का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी और ग्रीन मटीरियल्स







उत्तरप्रदेश में 15 जनवरी को मकर संक्रांति का अवकाश... योगी सरकार का ऐलान

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश सरकार ने मकर संक्रांति 2026 के मौके पर 15 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जारी अधिसूचना के अनुसार, सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल और राज्य संचालित संस्थान में 15 को अवकाश रहेगा। आमतौर पर मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है, लेकिन इस वर्ष सूर्य देव 14 को दोपहर 3-13 बजे मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। चूंकि संक्रांति के धार्मिक अनुष्ठान प्रायः सुबह होते हैं, इसलिए सभी शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए 15 जनवरी को पुण्यकाल सूर्योदय से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। इस मौके पर प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, उज्जैन, मेरठ और बिजनौर सहित उत्तर प्रदेश के प्रमुख गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। लोग गंगा और सरयू में पवित्र स्नान और दान करने वाले हैं। इसी तरह, ऋषिकेश और हरिद्वार में भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलेगी। मकर संक्रांति को खिचड़ी त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है और इस सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के दिन माना जाता है। इस बार शुभ मुहूर्त और धार्मिक परंपराओं के आधार पर 15 जनवरी को उत्सव मनाना उचित माना गया है।

अब्बास अंसारी को बड़ी राहत देकर सुप्रीम कोर्ट ने नियमित जमानत मंजूर की

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को बड़ी राहत देकर गैरस्टर एक्ट के मामले में नियमित जमानत मंजूर कर दी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सुर्यांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने उनकी अंतरिम जमानत को स्थायी किया। इससे पहले कोर्ट ने मार्च 2024 में उन्हें अंतरिम जमानत दी थी और सितंबर 2024 में जमानत की कुछ शर्तों में ढील भी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि अंसारी के सार्वजनिक रूप से बोलने पर कोर्ट पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। अंसारी जनप्रतिनिधि होने के नाते वे सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन अपने खिलाफ चल रहे विचारधीन मामलों पर सार्वजनिक टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने अनुमति दी थी कि वे लखनऊ स्थित अपने पुराने पते के बजाय किसी अन्य स्थान पर रह सकते हैं, बशर्ते इसकी सूचना यूपी पुलिस और निचली अदालत को दी जाए। अब्बास अंसारी पर अगस्त 2024 में मारपीट और जबरन वसूली के आरोपों के तहत उत्तर प्रदेश गैरस्टर्स एंड एंटी-सोशल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। इससे पहले वे अन्य आपराधिक मामलों में पहले ही जमानत पा चुके थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिसंबर 2024 में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन्हें बड़ी कानूनी राहत मिली है।

केंद्र ने एनआईए को सौंपी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़े मामलों की जांच

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़े मामलों की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के हाथों में सौंप दी है। यह मामला दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से एनआईए को स्थानांतरित किया है। सुओं के मुताबिक, एनआईए भारत में बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध घुसपैठ कराने वाले पुरे नेटवर्क, उसके ऑपरेटर्स और मनी ट्रेल की गहराई से जांच करेगी। एजेंसी इस मामले में जल्द एक नई एफआईआर भी दर्ज कर सकती है। दरअसल यह कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर की गई है, इसके बाद देशभर में अवैध घुसपैठ के खिलाफ सख्ती बढ़ गई है। जांच एजेंसियों का फोकस उन संगठित सिंडिकेट्स पर है, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत में अवैध रूप से प्रवेश दिलाने, ठहराने और उन्हें फजी दस्तावेज उपलब्ध करने की साजिश में लगे हुए हैं। सुओं ने बताया कि जांच के दायरे में फजी आधार कार्ड, वोटर आईडी और अन्य पहचान पत्र बनवाने वाला पूरा नेटवर्क है।

चार साल में 3 राज्यों में ईडी चुनाव से कुछ समय पहले कर चुकी है बड़ी कार्रवाई

-पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ईडी की बढ़ती सक्रियता को लेकर उठे सवाल

नई दिल्ली (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ईडी की बढ़ती सक्रियता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ताजा मामला कोलकाता में आई-पीएसी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी का है, जिसमें सीएम ममता बनर्जी और ईडी आमने-सामने आ गए हैं। बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होना है। इससे पहले 4 साल में 3 राज्यों झारखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र में ऐसा हो चुका है, जब ईडी ने पुराने मामलों में चुनाव से कुछ समय पहले बड़ी कार्रवाई की है। इस साल बंगाल समेत तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होना है। इसके साथ इन राज्यों में ईडी ने पुराने मामलों की फाइलें खोलना शुरू कर दिया है। तमिलनाडु में शराब, रियल एस्टेट और शेल कंपनियों से जुड़े मामले सत्ताधारी डीएमके के लिए परेशानी बन गए हैं। वहीं असम में बीजेपी की सरकार है। विपक्षी कांग्रेस और एआईयूडीएफ से जुड़े नेताओं पर कार्रवाई का डर चुनावी फंडिंग नेटवर्क पर असर डाल रहा है। केरल में सोना तस्करी और सहकारी बैंक मामलों से एलडीएफ सरकार घिरी हुई है। पुडुचेरी में कारोबारी और राजनीतिक

गठजोड़ पर एजेंसी की नजर है। बता दें झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद दबाव बना था। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने आप का ताना-बाना बिगाड़ दिया था। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी से जुड़े मामलों के बीच दल टूटे और सरकारें गिरा। कई बार चार्जशीट से पहले ही राजनीतिक समीकरण बदल गए। हालांकि ईडी का कहना है कि उसका काम केवल कानून के तहत जांच करना है, चुनाव से कोई लेना-देना नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में आई-पीएसी मामले 5 साल पुराना, लेकिन पहला छापा चुनाव से 2-3 महीने पहले मारा गया। ईडी ने कायला तस्करी से जुड़े 2,742 करोड़ के मनी-लॉन्ड्रिंग मामले के तहत 8 जनवरी को इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (आई-पीएसी) के कार्यालय और निर्देशक प्रतीक जैन के घर छापेमारी की थी। सीबीआई ने इस मामले में 27 नवंबर 2020 को एफआईआर दर्ज की थी। ईडी ने 28 नवंबर 2020 को इसकी जांच शुरू की थी। यह मामला अब 5वें साल में

है, लेकिन कार्रवाई ठीक उस वक्त सामने आई, जब बंगाल में मार्च-अप्रैल 2026 में चुनाव होने हैं। आई-पीएसी भारत की पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी है, जो राजनीतिक दलों के लिए बड़े स्तर पर चुनावी अभियानों का काम करती है। आरोप है कि 20 करोड़ हवाला के जरिए आई-पीएसी तक ट्रांसफर हुए। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार ने जांच में बाधा डाली और सबूत नष्ट किए। दिल्ली में 2022 के मामले में 2024 में सीएम अरेंद्र गुप्ता, 2025 में चुनाव थे। 2022 में शराब नीति मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में सीबीआई और ईडी जांच की शुरुआत हुई। फरवरी 2023 में इस मामले में मनीष सिंसोदिया और मार्च 2024 में तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। फरवरी 2025 में विधानसभा चुनाव हुए और बीजेपी सत्ता पर कब्जा हो गई। वहीं झारखंड में अगस्त 2023 में ईडी ने भूमि और मनी-लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। दिसंबर में पूछताछ हुई। जनवरी 2024 में ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को इस मामले में गिरफ्तार कर



लिया। इसके बाद उन्हें अपना सीएम पद छोड़ना पड़ा था। नवंबर 2024 में चुनाव हुए। हालांकि, हेमंत सोरेन की पार्टी जीती और वे फिर सीएम बन गए। महाराष्ट्र में 2021 के मामले में 3 साल बाद चुनाव से 6 दिन पहले छापेमारी की। 14 नवंबर 2024 को ईडी ने महाराष्ट्र और गुजरात में 23 स्थानों पर छापेमारी की और व्यापारी सिराज अहमद हारून मेमन से जुड़े 125 करोड़ रुपए के मनी-लॉन्ड्रिंग और चुनावी फंडिंग ट्रेल को खंगाला। 20 नवंबर 2024 को चुनाव से छह दिन पहले इस मामले में विपक्षी दलों पर नोट और वोट जिहाद के आरोप लगे। इस चुनाव में बीजेपी ने जी हासिल की।

फडणवीस के बयान पर संजय राउत का पलटवार... मराठी मानुष को ठाकरे परिवार से नहीं, भाजपा से खतरा

मुंबई (एजेंसी)। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान पर तीखा पलटवार कर कहा है कि मराठी मानुष को ठाकरे परिवार से नहीं, बल्कि भाजपा से खतरा है। सीएम फडणवीस द्वारा ठाकरे बंधुओं के «अस्तित्व खतरे में» होने की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देकर राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री को ठाकरे परिवार की नहीं, बल्कि अपनी राजनीति की चिंता करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ठाकरे परिवार



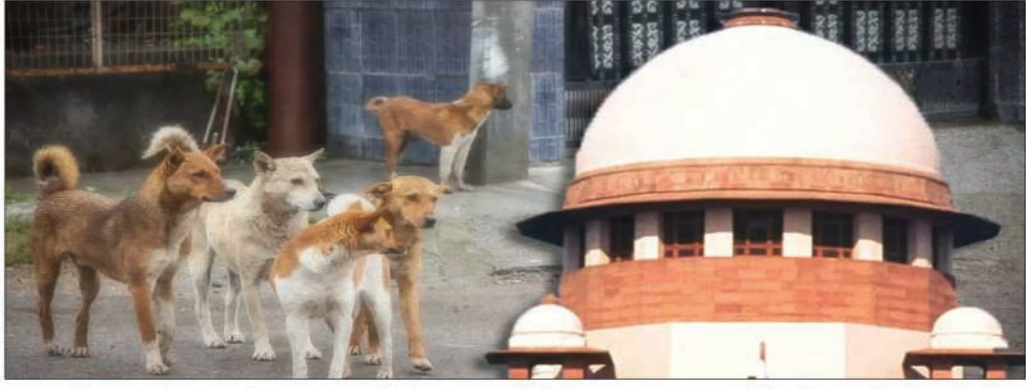
केवल ठाकरे बंधुओं का नहीं, बल्कि पूरे मराठी समाज का सवाल है। राउत ने कहा कि शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे ने ही भाजपा को महाराष्ट्र में मजबूती दी। यदि बालासाहेब न होते, तब भाजपा को कोई नहीं जानता। उन्होंने आरोप लगाया कि फडणवीस द्वारा ठाकरे बंधुओं पर सवाल उठाना, दरअसल बालासाहेब ठाकरे को चुनौती देने जैसा है। इसके

पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवाजी पार्क में संयुक्त रैली को संबोधित कर ठाकरे बंधुओं पर हमला बोला था। फडणवीस ने सवाल किया था कि यदि मराठी मानुष खतरे में हैं, तब पिछले 30 वर्षों में ठाकरे बंधुओं ने उसके लिए क्या बाढ़ते हैं। राउत ने आरोप लगाया कि मराठी मानुष का नहीं, बल्कि ठाकरे बंधुओं का अस्तित्व खतरे में है और बीएमपीसी का नया मेयर महायुति से, हिंदू और मराठी महाराष्ट्र में प्रासंगिक रहा है और यह

अगर कुत्ते के काटने से कोई मौत या घायल होता है तो सरकार पर होगा मुआवजा तय

-सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले पर सुनवाई करते हुए की अहम टिप्पणी

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले पर मंगलवार को अहम टिप्पणी की। बेंच ने चेतावनी दी कि अगर किसी कुत्ते के काटने से कोई मौत होती है या कोई घायल होता है, तो राज्य सरकार पर हर ऐसे मामले के लिए मुआवजा तय किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया। जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि जो लोग कुत्तों को खाना खिलाते का दावा करते हैं, उन्हें भी जवाबदेह ठहराया जाएगा। बेंच ने पूछा कि अगर आप कुत्तों को इतना चाहते हैं तो इन्हें अपने घर ले जाएं। कुत्ते सड़कों पर क्यों घूमें, लोगों को काटें और डराएं?



मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी के उस बयान के जवाब में आई, जिन्होंने कहा था कि आवारा कुत्तों का मुद्दा भावनात्मक है। बेंच लिखा, ने उनसे कहा कि भावनाएं अब तक सिर्फ कुत्तों के लिए ही लग रही हैं। इस पर गुरुस्वामी ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं है। मैं इसानों के बारे में भी उतना ही चिंतित हूं। कुत्ते के काटने की शिकायत एक महिला ने भी कोर्ट में अपना पक्ष

रखा। उन्होंने कहा कि मैं इस बात से सहमत हूं कि एनिमल वर्थ कंट्रोल कार्यक्रम को सही से लागू करने पर कुत्तों की आक्रामकता और उनकी संख्या को कम करने में मदद मिलेगी, लेकिन मुझे एक कुत्ते ने बिना किसी उकसावे के काट लिया था। महिला ने बेंच को बताया कि वह कुत्ता लंबे समय से क्रूरता का शिकार था। यह डर के कारण होने वाली स्वात्मक आक्रामकता थी। मैं किसी और के किए हुए

कार्यों की सजा भुगत रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि उसने सड़कों से हर कुत्ते को हटाने का निर्देश नहीं दिया और उसका निर्देश पशु जन्म नियंत्रण नियमों के तहत इन आवारा कुत्तों से निपटने में संबंधित था। आवारा कुत्तों के मामले में दलीलें सुनते हुए कोर्ट ने कहा कि कुत्ते उन लोगों को सूझ सकते हैं जो या तो उनसे डरते हैं या जिन्हें कुत्ते ने काटा हो और वे ऐसे लोगों पर हमला

कर देते हैं। सीनियर वकील ने कहा कि दिल्ली जैसे स्थानों में चूहों का प्रकोप है और दिल्ली में बंदरों से भी एक अनूठी समस्या है। कुत्तों को अचानक हटाने से चूहों की आबादी बढ़ जाएगी, जिसके गंभीर परिणाम होंगे। जज मेहता ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि कुत्ते और बिस्त्रियां दुश्मन हैं। बिस्त्रियां चूहों को मारती हैं। इसलिए हमें बिस्त्रियों की संख्या बढ़ानी चाहिए।

रांची प्रेस क्लब ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के साथ संवाद में भागीदारी के लिए सदस्यों का जताया आभार



प्रत्यूष नवबिहार संवाददाता

रांची : रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष शंभु नाथ चौधरी ने सोमवार को क्लब में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ला के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम की सफलता पर क्लब के सभी सदस्यों के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा कि रांची प्रेस क्लब में अहम श्रृंखला की शुरुआत एक विशिष्ट सोच के साथ हुई है। लोकतंत्र में संवाद जरूरी है, क्योंकि सचलों के माकूल जवाब चाहिए। संवाद

जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र की बुनियाद है अभिव्यक्ति। संवाद जरूरी है, क्योंकि चुप्पी रास्ता नहीं दिखाती। संवाद जरूरी है, क्योंकि विचार टकराते हैं, तो रास्ते निकलते हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ला ने राजनीति और मीडिया विषय पर सारगर्भित विचार रखे। कार्यक्रम के दौरान दोनों के बीच रिश्ते की पड़ताल की एक कोशिश हुई। उन्होंने कहा, जब राजनीति भटकती है, तो मीडिया का दायित्व



बढ़ जाता है। पत्रश्री बलबीर दत्त ने मीडिया पर बढ़ते बाजारवादी



दबाव पर चिंता जताई। वरिष्ठ पत्रकार बैजनाथ मिश्र ने विषय



प्रवेश कराया। उन्होंने राजनीति और पत्रकारिता में मूल्यों के क्षरण की चर्चा की। शहर के वरिष्ठ और युवा पत्रकारों की मौजूदगी ने संवाद को जीवंत, प्रासंगिक और अर्थपूर्ण बना दिया।